

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 2618

06 ; 2020 प्रश्न त

ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

2618. ल

श्री कर्पल मोरेश्वर पाटोल:

f f

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

() क ा ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को आवश्यकताओं का पता ि ई सवक्षण किया है;

() ि , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम द इस पर क्या अनुवर्ता कारवाई का गई है/किए ि ;

(ग) देश म स्वास्थ्य देखभाल को सुविधा रहित गांवां को राज्य/संघ ज क्षेत्र- ख ि ;

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों म श ि ा अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं म सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा ?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (. . .)

() (): ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यिकी जिसका प्रकाशन इस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के संबंध म सूचना प्रदान करती है जिसम मानव संसाधन और इसका कायशीलता का स्थिति शामिल है। यह रिपोर्ट राज्यां/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर प्रकाशित का जाती है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य परिचया संबंधी अवसंरचना का विकास एक तीन-प्रणाली के रूप म किया जाता है। स्वास्थ्य परिचया अवसंरचना के जनसंख्या के मानदण्डों के अनुसार, संपूण भारत म समतल क्षेत्रों म क्रमशः प्रति 5000 जनसंख्या हेतु एक उपकद्र, प्रति 30000 जनसंख्या हेतु एक प्रार्थामिक स्वास्थ्य कद्र और प्रति 120000 जनसंख्या हेतु

एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। इसके अलावा, समान जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार, भारत में पहाड़ी/ जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में क्रमशः प्रति 3000 जनसंख्या हेतु एक उप-केंद्र, प्रति 20000 जनसंख्या हेतु एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य खे 1 2018-19 के अनुसार(दिनांक 31 मार्च 2019 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 157411 -केंद्र (एससी), 24855 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) (इमम स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र सम्मिलित हैं) और 5335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ()

उपरोक्त के अलावा, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक उनको पहुंच में सुधारने करने हेतु सेवा प्रदानगी के लिए 1415 फी कायशील ह, इसके अतिरिक्त, आपातकालीन स्थिति में नजदीकी कायशील सुविधा केंद्र तक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में 25000 एम्बु फी

इसके अलावा, जनस्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के नाते, स्वास्थ्य परिचया सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने को प्राथमिक जिम्मेदारों संबंधित राज्य सरकारों को है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों सहित जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अवसंरचनागत सुदृढीकरण और पर्याप्त जन संख्या को तैनाती शामिल है। स्वास्थ्य परिचया संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाले लोगों के लिए सुगम्य, किफायती तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों के प्रयासों के सम्पूर्ण बनाता है।

एनएचएम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को मानदण्डों के अनुरूप नए सुविधा केंद्रों का स्थापना के लिए और उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना अन्तरालों को समाप्त करने के लिए मौजूदा सुविधा केंद्रों के उन्नयन तथा जन संसाधन को रिक्तियों को भरने के फी प्र

एनएचएम मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य परिवार नियोजन, सावभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और क्षय रोग, एचआईवी/एड्स, वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, ष्ट रोग आदि जैसे मुख्य रोगों के संबंध में निशुल्क सेवाओं के प्रावधान के फी प्र

() और (घ): ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यिका 2018-19 (फि 31 ; 2019) -केंद्र (ल - फी) 4 , प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एचडबल्यूसी- फी) 26

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीडबल्यूसी) 120 गांवों को कवर करता है। अतः सम्पूर्ण देश में सभी गांवों को भी भर्त्ति कवर किया जा चुका है।

भारत सरकार ने सम्पूर्ण भारत (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का उनको संबंधित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर विभिन्न क्रियालापों के लिए सहायता प्रदान करेगी।

सम्पूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए गैर-निर्धियां, वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों और रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) निर्धियां के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के निमाण और/ अथवा अवसंरचना के उन्नयन, स्थानीय (एमसीएच) विंग्स, ट्रोमा केंद्रों और प्रथम रेफरल इकाईयों के उन्नयन, रक्त कोषों के परिचालन आदि के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचनागत सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का परिचालन करना (दुर्गम क्षेत्रों में मानव संसाधनों का तैनाती, उपकरणों औरषधियां और नैदानिकों का आपूर्ति के माध्यम से)
- इसके अतिरिक्त कुछ नई पहल शुरु की गई हैं जैसे गैर-निर्धियां () । (एकमेव स्तनपान प्रोत्साहन हेतु), प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (निजी प्रदाताओं को स्वैच्छिक भागीदारों के जरिए विशेषज्ञ मातृत्व परिचया तक पहुंच में सुधार हेतु), प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलैसिस कार्यक्रम, आयुष्मान भारत कार्यक्रम (जिसमें स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एचडबल्यूसी) शामिल हैं) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (), निम्नलिखित () रूप से कवर की गई अथवा न की गई जनसंख्या को प्रतिरक्षण करना), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम (आरबीएसके), कार्याकल्प (जन स्वास्थ्य परिचया सुविधा केंद्रों में स्वच्छता, सफाई एवं संक्रमण नियंत्रण परिपाटियां तो प्रोत्साहित करना), प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल-लक्ष्य (प्रसूति कक्ष और मातृत्व ओटों में प्रसूति तैनाती परिचया के साथ संबद्ध रोकने योग्य मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर रूग्णता प्रभावों को कम करने संबंधी पहल), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) (रोकने योग्य सभी मातृ एवं नवजात मौतों को समाप्त करना)
